सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-771
27/12/2015

आपदा प्रबंधन के लिये बनेगा सुपर इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर :– मुख्यमंत्री

पटना, 27 दिसम्बर 2015 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज 7 सर्कुलर रोड स्थित कैम्प कार्यालय में आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। विभाग की ओर से बैठक में पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने समीक्षा के दौरान निदेश दिया कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से स्थापित किये जाने वाले इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर राज्य तथा जिला स्तर पर स्थापित किया गया है, उसमें आपदा से निपटने के लिये सभी आधुनिक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि इन सब के ऊपर राज्य में एक सुपर इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर स्थापित किया जायेगा, जो आपदा प्रबंधन के लिये सभी प्रकार के आधुनिकतम उपकरणों एवं संसाधनों से लैस रहेगा। यह सेन्टर निर्माणाधीन पुलिस भवन में स्थापित होगा। इसके लिये प्रोटोकॉल तय किया जायेगा। इस सेन्टर में बड़ी आपदा से निपटने की सारी व्यवस्थायें होगी। उन्होंने इसके लिये आपदा प्रबंधन विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवश्यकताओं का आकलन करने तथा एक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया। इसके नोडल अफसर के रूप में पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की जायेगी। उन्होंने कहा कि शताब्दी अन्न कलश योजना जारी रहेगी ताकि राज्य में भूख से किसी की मौत न हो। इस योजना के तहत उसे लाभ सुनिश्चित हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि बाढ़, सुखाड़, अगलगी, पेयजल संकट, भूकम्प आदि के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) की तरह चक्रवाती तूफान के लिये भी मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाय। उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एस0डी0एम0पी0) की तरह जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजना (डी0डी0एम0पी0) शीघ्र बना लेने का निदेश दिया। उन्होंने हर ऑफिस में भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान शीघ्र बना लेने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन हेतु सामग्री संसाधनों का सुदृढ़ीकरण करने का निर्देश दिया, इसके लिये राज्य एवं जिला स्तर पर जिन चीजों की व्यवस्था करनी है, उसे ससमय कर लिया जाय। इसमें लाइफ जैकेट, महाजाल, टेंट, बक्शा, बर्तन, नाव, इनफ्लैटेबुल मोटरवोट, टेंट, जी0पी0एस0 सेट, इनफ्लैटेबुल इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम, जीवन रक्षक एम्बुलेंस इत्यादि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से निपटने के लिये आपदा प्रबंधन हेतु मानव संसाधनों का प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रशिक्षण पहुँचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम को ज्यादा प्रशिक्षित किया जायेगा और इसमें रहने वाले चिकित्सक एवं पुलिस पदाधिकारी के लिये नॉर्म्स तैयार किये जायेंगे ताकि उनके तबादले से आपदा प्रबंधन पर कोई प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के जो कीट इन अधिकारियों को दिये जाते हैं, उनकी नियमित जॉच हो तथा उन्हें पी0एच0सी0 एवं थाना में रखा जाय।

मुख्यमंत्री ने इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, कॉन्ट्रैक्टर्स, राजमिस्त्री को भूकम्परोधी बिल्डिंग बनाने का प्रशिक्षण देने का कार्य बिपार्ड की जगह आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को करने का निदेश दिया है। इसके लिये मुख्य सचिव के स्तर पर एक बैठक संबंधित विभागों की बुलाकर

एक निर्देश जारी किया जायेगा। उन्होंने स्कूली बच्चों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण जारी रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर भी लोगों को चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाय ताकि ये लोग मास्टर ट्रेनर बनकर गॉव के लोगों को प्रशिक्षित करें। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन हेतु टेक्नोलॉजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने विभाग द्वारा 19 जिलों में अपर समाहर्ता के पद की स्वीकृति प्रदान करने पर भी सहमति दी। 8 एवं 9 जनवरी को विशेष रोड मैप फॉर डी0आर0आर0 के प्रारूप को अंतिम रूप देने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग एक कार्यशाला का आयोजन कर रही है, जिसमें राज्य एवं राष्ट्र स्तर के विशेषज्ञों की भागीदारी होगी। विभागीय प्रधान सचिव के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने इस कार्यशाला के उद्घाटन हेतु सहमति प्रदान की है।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अलावे आपदा प्रबंधन मंत्री श्री चन्द्रशेखर, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री पी0के0 ठाकुर, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन श्री ब्यासजी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

******